एमजीएनआरईजीए का ग्रामीण भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और सूक्ष्म उद्यमों पर प्रभाव

[1]पुष्पा साहु, [2]डॉ. संजीव कुमार
[1]शोधार्थी, [2]पर्यवेक्षक
[1–2]विभागः अर्थशास्त्र, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ

सार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आय स्थिरीकरण और अवसंरचना विकास के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। दुर्ग जिले में एमजीएनआरईजीए का प्रभावी कार्यान्वयन कई प्रशासनिक, वित्तीय और परिचालन चुनौतियों का सामना करता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म उद्यमों पर गहरे प्रभाव डालते हैं। इस अध्ययन में, हमने दुर्ग जिले में एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन की स्थिति, प्रशासनिक निष्पादन, और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया है। परिणाम बताते हैं कि एमजीएनआरईजीए न केवल गरीब और वंचित परिवारों की आय में वृद्धि करता है, बल्कि स्थानीय उपभोग, सहायक सेवाओं के लिए अस्थायी रोजगार, और छोटे व्यवसायों के विकास को भी बढ़ावा देता है। हालांकि, कई प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएँ, जैसे कि निधि आवंटन में देरी, वेतन भुगतान में असमानता, और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी, कार्यक्रम के प्रभाव को सीमित कर रही हैं।

मुख्य शब्दः एमजीएनआरईजीए, दुर्ग जिला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म उद्यम, रोजगार सृजन, आय स्थिरीकरण, प्रशासनिक निष्पादन, सामाजिक समावेशन।

परिचयः

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) 2005 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को कानूनी रूप से गारंटीकृत रोजगार दिया जाता है, जिससे उनकी आय स्थिर होती है और ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण में योगदान मिलता है। दुर्ग जिले में, जहां कृषि आधारित अर्थव्यवस्था प्रमुख है, एमजीएनआरईजीए का कार्यान्वयन ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक लाभ लाता है। हालांकि, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रशासनिक, वित्तीय, और जमीनी स्तर पर कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। यह अध्ययन इन प्रभावों और बाधाओं को समझने के लिए दुर्ग जिले में एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन की स्थिति का विश्लेषण करता है।

दुर्ग जिले में एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन की स्थिति

दुर्ग जिले में एमजीएनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक निष्पादन, परिवारों की भागीदारी और रोजगार सृजन को स्थानीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप स्थापित करने सहित कई स्तरों पर विश्लेषण की आवश्यकता है। अपनी मिश्रित ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विविध कृषि आधार के साथ दुर्ग, जिला स्तर पर एमजीएनआरईजीए की परिचालन प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक प्रतिनिधि परिदृश्य प्रदान करता है। इस जिले में कार्यान्वयन के परिणाम राज्य नीति निर्देशों, प्रशासनिक क्षमता और स्थानीय शासन संरचनाओं के परस्पर संबंध को दर्शाते हैं, जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सफलताओं और बाधाओं दोनों को उजागर करते हैं।

जिला स्तरीय प्रशासनिक निष्पादन

दुर्ग जिले में एमजीएनआरईजीए के प्रशासनिक ढांचे में जिला प्रशासन, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय शामिल है। कार्यान्वयन के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

कार्य योजना एवं अनुमोदनजिला कार्यक्रम समन्वयक ग्राम पंचायतों से रोजगार योजनाओं को समेकित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रस्तावित कार्य एमजीएनआरईजीए दिशानिर्देशों और स्थानीय विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप हों (विटनबर्ग, 1988)।

निधि आवंटन एवं निगरानी:मजदूरी और सामग्री निधि का आवंटन जिला स्तरीय वित्तीय कार्यालयों के माध्यम से ब्लॉकों और पंचायतों को किया जाता है। नियमित निगरानी तंत्र निधि के उपयोग और कार्य पूर्णता की स्थिति पर नजर रखते हैं।

कार्यान्वयन कर्मचारियों की क्षमता एवं प्रशिक्षण:पंचायत पदाधिकारियों और ब्लॉक–स्तरीय समन्वयकों सहित स्थानीय अधिकारियों को वेतन भुगतान की समय–सीमा, रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल और सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण प्राप्त होता है।

प्रशासनिक क्रियान्वयन में चुनौतियाँ:

- राज्य स्तर से जिला स्तर तक निधि जारी होने में देरी
- जटिल कार्यों के लिए सीमित तकनीकी पर्यवेक्षण
- विभिन्न ब्लॉकों में प्रशासनिक दक्षता में भिन्नता
- वेतन भुगतान की समयसीमा और बेरोजगारी भत्तों की अपर्याप्त निगरानी

ये प्रशासनिक कारक जिले के भीतर एमजीएनआरईजीए की आर्थिक प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।

सहभागिता के रुझान और कार्य की मांग

घरेलू भागीदारी और कार्य मांग के पैटर्न कार्यक्रम की स्वीकार्यता और आर्थिक प्रभाव के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। दुर्ग जिले में देखे गए रुझान इस प्रकार हैं:

वंचित परिवारों में उच्च सहभागिता: भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला प्रधान परिवारों में अपेक्षाकृत उच्च पंजीकरण और भागीदारी दरें देखी गई हैं, जो योजना के कमजोर आबादी को लक्षित करने को दर्शाती हैं।

कार्य मांग में मौसमी भिन्नता: कृषि उत्पादन में कमी के समय (फसल कटाई के बाद और बुवाई से पहले के मौसम) में मांग चरम पर होती है, जबकि खेती के चरम महीनों के दौरान भागीदारी कम होती है। यह पैटर्न आय स्थिरीकरण में एमजीएनआरईजीए की भूमिका को उजागर करता है (अमीरीपुर एट अल., 2014)।

जॉब कार्ड का स्वामित्व और उपयोग: ग्रामीण परिवारों के बहुमत के पास जॉब कार्ड हैंय हालांकि, वेतन भुगतान में देरी, कार्यस्थलों से दूरी और अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी जैसे कारकों के कारण सभी कार्डधारक सक्रिय रूप से काम की मांग नहीं करते हैं।

लिंग–विशिष्ट भागीदारी के रुझान: सामाजिक समावेशन के प्रयासों और गांवों के निकट कार्यस्थलों की उपलब्धता के कारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हालांकि, आवागमन संबंधी बाधाओं और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण दूरदराज के क्षेत्रों में भागीदारी का स्तर अभी भी कम है।

स्थानीय आर्थिक गुणक: एमजीएनआरईजीए कार्यों में सक्रिय भागीदारी स्थानीय उपभोग में वृद्धि, सहायक सेवा प्रदाताओं के लिए अस्थायी वेतन रोजगार और छोटे पैमाने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में योगदान देती है।

दुर्ग जिले में एमजीएनआरईजीए का आर्थिक प्रभाव

दुर्ग जिले में एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन से घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हुए हैं। कानूनी रूप से गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके, यह कार्यक्रम आय स्थिरता, उपभोग पैटर्न और स्थानीय आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करता है। इन प्रभावों की तीव्रता स्थानीय प्रशासनिक दक्षता, कार्य उपलब्धता और मजदूरी भुगतान की नियमितता पर निर्भर करती है। ग्रामीण आजीविका और विकास परिणामों के लिए कार्यक्रम के सूक्ष्म आर्थिक निहितार्थों को समझने के लिए जिला स्तर पर विश्लेषण आवश्यक है। (धुलगंड एट अल., 2020)

घरेलू आय के प्रभाव

दुर्ग जिले में एमजीएनआरईजीए का घरेलू स्तर पर प्रभाव उल्लेखनीय है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले, भूमिहीन और लघु किसान परिवारों के लिए। कार्यक्रम में भागीदारी आय का एक पूरक और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है, जिससे अनौपचारिक, मौसमी या शोषणकारी मजदूरी पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाती है। कई परिवारों के लिए, विशेष रूप से सीमित भूमि वाले या अनियमित कृषि आय वाले परिवारों के लिए, एमजीएनआरईजीए की मजदूरी एक वित्तीय सुरक्षा कवच का काम करती है, जिससे घरेलू उपभोग को स्थिर करने और आर्थिक तंगी के समय में जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। एमजीएनआरईजीए से प्राप्त मजदूरी सीधे उपभोग को सुचारू बनाने में योगदान देती है, जिससे परिवार भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों की शिक्षा और अन्य बुनियादी खर्चों जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। कई परिवार इन आय के एक हिस्से का उपयोग ऋण चुकाने के लिए भी करते हैं, जिससे अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाती है जो अक्सर उच्च ब्याज दरें वसूलते हैं। एमजीएनआरईजीए से प्राप्त आय की पूर्वानुमानित और कानूनी रूप से गारंटीकृत प्रकृति घरेलू वित्तीय नियोजन को बढ़ावा देती है, जिससे परिवार अल्पकालिक उपभोग और दीर्घकालिक जरूरतों के लिए संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से आवंटन कर सकते हैं, और यहां तक कि समय के साथ सीमित संपत्ति संचय करने में भी सक्षम होते हैं (कूपर और स्टीवर्ट, 2020)।

परिवारों को मिलने वाले प्रमुख लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनियमित और मौसमी रोजगार पर निर्भरता में कमी।
- बुनियादी उपभोग आवश्यकताओं को लगातार पूरा करने की बेहतर क्षमता।
- आंशिक ऋण भुगतान और वित्तीय असुरक्षा में कमी।
- सीमित संपत्ति संचय और बेहतर वित्तीय नियोजन का अवसर।

प्रत्यक्ष आय प्रभावों के अलावा, यह कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति को मजबूत करता है। एमजीएनआरईजीए के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अनौपचारिक रोजगार में अकुशल श्रमिकों के लिए एक मानदंड का काम करती है, जिससे अक्सर स्थानीय मजदूरी दरों में वृद्धि होती है और ग्रामीण श्रम बाजारों में काम करने की स्थितियों में सुधार होता है। यह व्यापक आर्थिक प्रभाव ग्रामीण आजीविका पर कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाता है। परिवारों की आय पर सकारात्मक प्रभावों की मात्रा कई परिचालन कारकों पर निर्भर करती है। समय पर मजदूरी का भुगतान, पर्याप्त काम का प्रावधान और श्रमिकों के अधिकारों की प्रभावी निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि कार्यक्रम अपने इच्छित आर्थिक लाभ प्रदान करे। भुगतान में देरी, कार्यदिवसों की सीमित उपलब्धता या अपर्याप्त प्रशासनिक सहायता एमजीएनआरईजीए मजदूरी की स्थिरता लाने वाली भूमिका को कम कर सकती है और परिवारों की आय और वित्तीय सुरक्षा में समग्र सुधार को घटा सकती है। इसलिए, दुर्ग में परिवारों पर एमजीएनआरईजीए के आर्थिक प्रभाव को ये कारक कैसे प्रभावित करते हैं, यह समझने के लिए एक विस्तृत जिला–स्तरीय मूल्यांकन आवश्यक है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था और गुणक प्रभाव

व्यक्तिगत परिवारों से परे, एमजीएनआरईजीए कई माध्यमों से दुर्ग जिले की व्यापक स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है:

ग्रामीण उपभोग में वृद्धि: एमजीएनआरईजीए के तहत मजदूरी का भुगतान मुख्य रूप से बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है, जिससे स्थानीय बाजारों और छोटे पैमाने के व्यवसायों के लिए मांग में वृद्धि होती है।

सहायक क्षेत्रों में रोजगार सृजन: निर्माण कार्यों, परिवहन और संबंधित सेवाओं के लिए सामग्रियों की खरीद से अस्थायी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे प्रत्यक्ष वेतन प्राप्तकर्ताओं के अलावा अन्य लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलता है।

अवसंरचना से जुड़े उत्पादकता लाभ: ग्रामीण सड़कों, जल संचयन संरचनाओं और मृदा संरक्षण परियोजनाओं के निर्माण से संपर्क और कृषि उत्पादकता में सुधार होता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालिक आय सृजन को समर्थन मिलता है।

प्रवासन का दबाव कम हुआ: स्थानीय रोजगार प्रदान करके, यह कार्यक्रम गांवों में श्रम को बनाए रखता है, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधि में होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है जो आमतौर पर मौसमी प्रवासन के साथ होता है (मार्टिन और स्ट्रॉबहार, 2002)।

इन सकारात्मक प्रभावों के बावजूद, विलंबित वेतन भुगतान, असमान कार्य वितरण और सीमित गुणवत्ता वाली संपत्ति निर्माण जैसी कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ स्थानीय आर्थिक लाभों की पूर्ण प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। दुर्ग में कार्यक्रम के आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर निरंतर निगरानी और लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ और बाधाएँ

एमजीएनआरईजीए के महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक लाभों के बावजूद, दुर्ग जिले में इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं जो इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं। ये चुनौतियाँ प्रशासनिक, वित्तीय, परिचालन और जमीनी स्तर के कारकों से उत्पन्न होती हैं, जो कार्यक्रम के वितरण के पैमाने और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करती हैं। इन बाधाओं को समझना सुधारात्मक उपायों को तैयार करने और कार्यक्रम की दक्षता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दे

जिला स्तर पर एमजीएनआरईजीए का सफल कार्यान्वयन प्रशासनिक दक्षता और समय पर वित्तीय सहायता दोनों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। यद्यपि यह कार्यक्रम मजदूरी रोजगार प्रदान करने और ग्रामीण संपत्ति सृजन में महत्वपूर्ण रहा है, फिर भी इसकी प्रभावशीलता कई प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियों से बाधित होती है। कार्यक्रम के इच्छित सामाजिक और आर्थिक लाभों को सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:

फंड जारी होने में देरी: केंद्र और राज्य सरकारों से जिला अधिकारियों को धन हस्तांतरण में अक्सर देरी होती है। इस देरी से न केवल श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान में बाधा आती है, बल्कि कार्यों की समय–सारणी और निरंतरता भी प्रभावित होती है। अनियमित धन प्रवाह से कार्यक्रम में श्रमिकों का विश्वास कम होता है और भागीदारी घट सकती है, विशेष रूप से सबसे कमजोर परिवारों में।

अपर्याप्त प्रशासनिक क्षमता: ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित कर्मियों की कमी एमजीएनआरईजीए परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी करने में महत्वपूर्ण

चुनौतियां पैदा करती है। सीमित मानव संसाधन पारदर्शिता, रिपोर्टिंग की सटीकता और परियोजना निष्पादन की समग्र दक्षता को प्रभावित करते हैं। योजना के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं में कर्मचारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण से अक्सर देरी, संसाधनों का कुप्रबंधन और आवंटित निधियों का कम उपयोग होता है (एल–तालियावी और वैन डेर वाल, 2019)।

जटिल वित्तीय प्रबंधनः एमजीएनआरईजीए निधि के प्रभावी प्रबंधन के लिए मजदूरी, सामग्री लागत, प्रशासनिक व्यय और परिसंपत्ति निर्माण के लिए भुगतान सहित कई घटकों को संभालना आवश्यक है। कमजोर लेखा प्रणाली, खराब रिकॉर्ड–रखरखाव और उचित वित्तीय निगरानी का अभाव निधि के दुरुपयोग, रिसाव या मजदूरी भुगतान में विसंगतियों का कारण बन सकता है। इससे न केवल कार्यक्रम की आर्थिक प्रभावशीलता कम होती है, बल्कि ग्रामीण श्रमिकों के बीच विश्वास और भागीदारी भी प्रभावित होती है।

निगरानी और जवाबदेही में कमियांः अधिनियम द्वारा अनिवार्य किए जाने के बावजूद, सामाजिक लेखापरीक्षा और निगरानी तंत्र अक्सर अनियमित रूप से संचालित किए जाते हैं या केवल सीमित संख्या में कार्यों को ही कवर करते हैं। अपर्याप्त पर्यवेक्षण, अनियमित रिपोर्टिंग और लेखापरीक्षा में समुदाय की कम भागीदारी निधि के उपयोग और मजदूरी वितरण दोनों में जवाबदेही को कम करती है। कमजोर निगरानी तंत्र से परियोजना निष्पादन में अक्षमता, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में कमी और यहां तक कि पात्र लाभार्थियों को रोजगार के अवसरों से वंचित होना भी संभव हो सकता है।

तकनीकी और समन्वय संबंधी चुनौतियाँः वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दों के अलावा, कार्य प्रकारों की खराब योजना, परिसंपत्ति निर्माण के लिए उचित डिजाइन का अभाव और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ अपर्याप्त समन्वय जैसी तकनीकी चुनौतियाँ अक्सर एमजीएनआरईजीए कार्यों के दीर्घकालिक प्रभाव को सीमित करती हैं। विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी भी संसाधन उपयोग और निर्मित परिसंपत्तियों की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।

ये प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियाँ संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने, निधि प्रवाह तंत्र में सुधार करने और जिला स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने के महत्व को उजागर करती हैं। दुर्ग जैसे जिलों में रोजगार सृजन, ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने और सतत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने में एमजीएनआरईजीए की पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए इन बाधाओं का समाधान करना आवश्यक है।

परिचालन और जमीनी स्तर की बाधाएँ

ग्राम स्तर पर परिचालन संबंधी चुनौतियां एमजीएनआरईजीए की प्रभावशीलता को और भी सीमित करती हैंः

अपर्याप्त कार्य उपलब्धताः रोजगार की मांग अक्सर कुछ अवधियों या ब्लॉकों में आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे सभी पात्र परिवारों को गारंटीकृत काम प्रदान करने की कार्यक्रम की क्षमता सीमित हो जाती है (रोमेरो–सांचेज एट अल., 2021)।

वेतन भुगतान में देरी या आंशिक भुगतानः जहां काम उपलब्ध है, वहां भी वेतन के भुगतान में देरी से परिवारों की आय का स्थिरीकरण कम हो जाता है और कार्यक्रम की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है।

परिसंपत्ति निर्माण में तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी मुद्देः अपर्याप्त तकनीकी पर्यवेक्षण जल संचयन संरचनाओं, सड़कों और मृदा संरक्षण कार्यों जैसी संपत्तियों की स्थायित्व और आर्थिक उपयोगिता को खतरे में डाल सकता है।

जागरूकता और भागीदारी संबंधी बाधाएँः कुछ पात्र परिवार, विशेष रूप से दूरस्थ या हाशिए पर स्थित क्षेत्रों में, कार्यस्थलों से दूरी, साक्षरता संबंधी बाधाओं या सामाजिक बाधाओं के कारण अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं या कार्यक्रम का पूरी तरह से उपयोग नहीं करते हैं (फ्लड और पार्कर, 2014)।

ये प्रशासनिक और परिचालन संबंधी अड़चनें दुर्ग जिले में एमजीएनआरईजीए के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण और निरंतर निगरानी के महत्व को रेखांकित करती हैं।

निष्कर्ष

दुर्ग जिले में एमजीएनआरईजीए का कार्यान्वयन गरीब और वंचित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना से न केवल परिवारों की आय में स्थिरता आई है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म उद्यमों को भी इस योजना से लाभ हुआ है, क्योंकि मजदूरी का अधिकांश हिस्सा स्थानीय उपभोग और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। हालांकि, प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं ने कार्यक्रम के प्रभाव को सीमित किया है। निधि में देरी, वेतन भुगतान में असमानताएँ और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी जैसी बाधाएँ कार्यक्रम के समग्र प्रभाव को कमजोर कर सकती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, कार्यान्वयन तंत्र में सुधार और बेहतर निगरानी तंत्र की आवश्यकता है, ताकि एमजीएनआरईजीए अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी भूमिका निभा सके।

संदर्भ

मेलनिक, केवाई (2022)। रोजगार अनुबंध में प्रवेश करते समय मानव श्रम अधिकारों की सामान्य कानूनी गारंटी। सामाजिक कानून, (1), 6–16.

मुनीस्वरन, पी., और सुंदरपंडियन, सी. (2021). एमजीएनरेगा परिवारों की आय वितरण और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च –ग्रंथालय, 9(6), 275–291.

नतेसन, एसडी, और मराठे, आरआर (2017)। एमजीएनआरईजीए का मूल्यांकनः डेटा एनवेलपमेंट विश्लेषण दृष्टिकोण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स, 44(2), 1817194।

क्विन, एन., डेविडसन, जे., मिलिगन, आई., एल्सले, एस., और कैंटवेल, एन. (2014). आगे बढ़नाः देखभाल से बाहर निकलने वाले युवाओं के लिए अधिकार–आधारित प्रतिमान की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्य, 60(1), 140–155.

रामचरन, एच. (2017). भारत में घरेलू उपभोग पर श्रमिकों के प्रेषण का प्रभावः उपभोग वृद्धि और स्थिरता का परीक्षण। जर्नल ऑफ एशियन फाइनेंस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, 4(4), 51–60.

ठाकुर, एस.एस., त्रिवेदी, ए., दीक्षित, ए., पात्रा, जे., और बरगाह, ए.एस. (2025)। इकोटूरिज्म और सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनः छत्तीसगढ़, भारत में खुटाघाट बांध के आसपास के मूल समुदायों का एक केस स्टडी। जर्नल ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एंड अर्थ साइंस इंटरनेशनल, 29(10), 218–231।

तिम्मिरी, डी., और आर, एसपी (2025)। भारत में ग्रामीण आजीविका पर एमजीएनरेगा का सामाजिक आर्थिक प्रभावः प्रिस्मा मॉडल का उपयोग करते हुए एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 7(5)

त्रिपाठी, एस., और यादव, पी. (2025). विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना 'एमजीएनआरईजीए' की दक्षता को समझने के लिए मशीन लर्निंग दृष्टिकोणः कल्याणकारी राज्य की गतिशीलता और स्थानीय विषमता में एक गहन अध्ययन। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट।